SHRI CHITTA BASU (Barasat) : The Government must taken note of the deep resentment about the price rise in Tamil Nadu. We all feel, and the House feels that there is a very serious situation prevailing in Tamil Nadu. That is due to the price rise, which is the result of the Government of India's policies. The Government of India should take a note of it, and must make a statement in this House... (*Interruptions*).

SHRI ABDUL RASHID KABULI : It appears that the ruling party there and the Congress (I) have reached some understanding, and that is why they are dending this here and are not coming with a statement. They must take the House into confindence ...(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : You have expressed your views and concern, it has been taken note of by the Government.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : I am sorry, the feelings expressed by a section of the House cannot be construed as the feelings of the House. These are the feelings of a few Members in this House. Unfortunately, the hon. Members are setting a very bad precedent. I am prepared, but Shri Kabuli should also be prepared. What is happenning in Jammu and Kashmir...(*Interruptions*).**

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. Now, we will go to the Private Members' Business.

16.22 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(SIXTY SEVENTH REPORT)

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I beg to move :

"That this House do agree with the Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th December, 1982."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That this House do agree with Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th December, 1982."

The motion was adopted.

16.23 hrs.

RESOLUTION RE: INDUSTRIAL SICKNESS CONTD.

MR. CHAIRMAN : (SHRI SOMNATH CHATTERJEE) : The House will now take further discussion on the Resolution moved by Shri E. Balanandan on 19th Aught, 1983.

Shri M.C. Daga to continue his speech. You have already taken 22 minutes, please complete it within 10 minutes. The balance time left for this is only 58 minutes.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, प्रस्ताव पेश किया है उसको पढ़ने समय नहीं लगाना चाहता, और यही कहना चाहता हूं कि अभी भी देश के अन्दर काफी रुग्ण कारखाने हैं। 10 दिसम्बर, 1983 को सदन के अन्दर जवाब देते हुए कहा गया था और रिजर्व बैंक की भी रिपोर्ट के अनुसार 371 बम्बई के कारखानों में से 193 कारखाने बीमार हैं। यह 10 दिसम्बर, 1983 के आँकड़े हैं, इतने कारखाने आज भी बीमार हैं।

हमारे लेबर मिनिस्टर ने कहा था :

"The latest data available with the Labour Ministry reveals that

> the total number of sick units increased by nearly 27 per cent between December 1979 (22366) and June 1982 (28363) while sickness in medium units showed a decline (1013 to 994), sickness was on the increase in large units (378 to 422) as also in small units (20975 to 25342)."

हमारे लेबर मिनिस्टर ने खुद कहा है कि इतने कारखाने आज भी बीमार हैं :

> "Available information for 1980 and 1981 indicates that the incidence of sickness among large units has been the highest in West Bengal, closely followed by Maharashtra."

मेरा कहना यह है कि आज इण्डस्ट्रीज की हालत बड़ी खराब है। कारखानों के बन्द होने से बड़ा नुकसान हो रहा है और बीमार कारखाने दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि बहुत सारी लेबर यूनियन्स बन गई हैं जोकि लेबर को कन्ट्रोल नहीं कर सकती हैं। आज हर एक आदमी नेता बन जाता है और लेबर लीडर बनकर अपना नाम पैदा करने के लिए कोई न कोई हड़ताल करा देता है।

पब्लिक सेक्टर का जो कांसेप्ट था उसके सम्बन्ध में 12 दिसम्बर को "इंडियन वर्कर" एक आर्टिकल छपा है जिसको मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हड़तालें करवाई जाती हैं और कौन लोग लीड करते हैं।

> "There is also the lack of awareness to organise thesmselves so as to earn their legitimate status in the industrial structure as well as to safe-guard themselves from exploitation.
>
> The trade union movement in our country has been built on economism. Because of its political orientation, the movement stands divided under varied political hues and the resultant competetive unionism hardly provides a representative character. The intra-union and inter union rivalry, which speaks poorly of their ability to appreciate the importance of the unity of approach of workers' problems.
>
> The leadership continues to be with the outsiders. The key executive posts at many critical levels are occupied mostly by the middle class intellectuals with clearcut political orientation lending the trade union a political colour."

इस प्रकार की हालत आजकल हो गई है कि जिनका वहां कोई काम नहीं है, जो लेबर लाज को भी नहीं समझते हैं वे भी लीडर बन जाते हैं। उनका काम हड़ताल कराना होता है। आगे उन्होंने कहा है कि ट्रेड युनियन्स एक सिर दर्द बन गई हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रकार से तमाम ट्रेड यूनियन्स न होकर, एक उद्योग में एक ही ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। उसे वर्कर्स का और उद्योग का भी लाभ हो सकेगा। हर फैक्टिरी में कई कई यूनियन्स होने से बहुत नुकसान होता है।

इंडियन वर्कर के 9 मई, 1983 के अंक में एक आर्टिकल आया था :

> "The present system of encouraging the mushroom growth of trade unions is the legacy of the erstwhile Janata Party Government. The up and coming trade union leader has also not spared the present Government for its lack of necessary political will to check the indiscriminate growth of trade unions."

जब जनता पार्टी का राज आया, उस समय नई-नई पार्टियां पैदा हुई और काफी यूनियनें पैदा कर दी गई। हर यूनियन का मकसद केवल हड़ताल करना है। हड़ताल होने की बजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। Indian Express' of 4th December 1982 says :

"Mr Mukherjee pointed out that the normal public secror statistics referred only to Central undertakings. But the worst performers were State run units-the electrcity boards, transport undertakings and irrigation systems. These lose huge sums every year-more than Rs. 2.000 crores..."

किसी भी जगह पर यूनियन न होने से ज्यादा नुकसान हो रहा है।

"Commerce" dated 15.5.1982 says :

"According to the Parliamentary Committee on Public Undertakings, out of 150 units under production in 1981-82 for which data were available, 12 recorded capacity utilisation of less than 50 per cent."

ज्यादा यूनियन होने की वजह से देश का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कई फैक्ट्रीज में 50 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं होता है। यह नुकसान केवल तथा कथित लीडरों के पैदा होने की वजह से होता है, क्योंकि वे हड़ताल कराने में विश्वास रखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसको इस पर चैक लगाना चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, श्री ई० बाला नन्दन जी ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिजोल्यूशन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

वस्तुत: जितने भी सरकारी उपक्रम हैं और साथ ही साथ प्राइवेट सैक्टर में जितनी भी इकाइयां हैं, वे प्राय: किसी न किसी कारण से धीरे-धीरे बीमार हो रही हैं। बीमार होने के कारण विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न बताए हैं। श्रमिक समस्याओं का समाधान न होने के कारण औद्योगिक, अशान्ति पैदा हो जाती है। समस्यायें चाहे बोनस की हों, बढ़ोतरी की हो, पदोन्नति की हो, जब उनको प्रबन्ध के द्वारा दबाया जाता है, तो ये चीजें पैदा होती हैं। जब इस तरफ मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित किया जाता है और काम समय पर नहीं होता है, तो हड़तालें होती हैं। अनेक प्रकार के नोटिसेस दिए जाने के बाद भी मैनेजमेंट कोई विशेष रुचि नहीं लेता है और मजदूरों पर दमनचक्र चलता रहता है। ऐसी परिस्थिति में चाहे श्रम मंत्रालय के अधिकारी हों, लेबर सुपरिन्टेडेंट हो, लेबर कमीशनस हो, ये लोग किसी न किसी रूप में मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं, माहवारी कुछ इस तरह की बंधी होती है, कि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। श्रमिकों की जब उपेक्षा की जाती है, तो फिर हड़तालें शुरू हो जाती हैं। जिसकी बजह से उत्पादन कम हो जाता है और उद्योग सिक हो जाते हैं। सिक होने के बाद सरकार को तो इलाज करना ही है, अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय हित को देखते हुए सरकार को सारे खर्च को भुगतना पड़ता है। आज सारे देश में 90 हजार रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं जिन में हजारों की संख्या में बीमार होती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण— अभी हमारे डागा जी बतला रहे थे—यूनियन के लोग हैं। मैं उनके इस तरह के आरोप से सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे समझता हूं कि इस में सरकार की ओर से तत्परता नहीं बरती जाती है। श्रम विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं वे मजदूरी की उचित मांगों की ओर ध्यान नहीं दिलाते हैं। मैं आप के सामने एक उदाहरण रखता हूं— बिहार में डालमियानगर में रोहतास इण्डस्ट्रीज हैं। वहां 6-7 कारखाने हैं— जिन में पेपर, सीमेंट, वनस्पति, कैमिकल, स्टील आदि का निर्माण होता है। इन कारखानों में कुल मिलाकर 15 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को दो वर्ष से— 1981-82 और 1982-83 का बोनस नहीं दिया गया है। वहां के मजदूरों

ने मैनेजमेंट के सामने पाँच माँगे रखी और उन के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सब संबंधित लोगों को सूचना दी गई कि कानून में जो प्रावधान किया गया, उसके अनुसार हम लोगों को दिलाया जाय । इन संस्थानों में 90 से 95 प्रतिशत सरकार और जनता की पूंजी लगी हुई है । करोड़ों रुपए के बिहार सरकार के बिजली के बिल उनकी तरफ बाकी हैं । वे लोग उन कारखानों की पूंजी डाइवर्शन करके दूसरे उद्योगों में लगाते जा रहे हैं और अब 7-12-1983 से वहां पर लाक-आउट कर दिया गया है । इसके पहले अपनी पांच माँगों को लेकर कानून के अनुसार विधिवत सूचनायें देकर जब मजदूरों ने हड़ताल की तो बिहार सरकार ने कहा कि हड़ताल उठा लो, तुम लोगों की मांगों के लिए विचार किया जायेगा । हड़ताल उठाई गई, तो मिल-मालिकों ने तुरंत वहाँ तालाबन्दी कर दी, जिस के कारण वहां के 15 हजार मजदूर बेकार हो गए । आज वहां बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई । कानून के अनुसार उन को जो बोनस दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया, कानून के अनुसार मजदूरों को जो तरक्की दी जानी थी वह नहीं दी गई । पेपर-मिल में 500 मजदूरों को "रोस्टर-ड्यूटी" पर रखा गया है । आप जानते हैं रोहतास नगर की पेपर इन्डस्ट्री सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है और उस में करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता रहा है, लेकिन फिर भी 500 मजदूरों को रोस्टर-ड्यूटी पर रख कर उनका शोषण किया जा रहा है, उनको परमानेन्ट नहीं किया जाता है इसी तरह से वहाँ पर जो दूसरे उद्योग हैं उन में भी डिप्लायमेंट-पूल में मजदूरों को रख कर उनका शोषण किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार को लिखा जाता है, लेबर मिनिस्टर को लिखा जाता है, राज्य सरकार को लिखा जाता है लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है । सब चुप बैठे हैं, शायद सब को कुछ मिलता होगा । सरकार ने जब उनको कहा कि हड़ताल उठा लो, तुम्हारी मांगों पर विचार कराया जाएगा, फिर सरकार क्यों चुप बैठी है, क्यों उनको तालाबन्दी करने दिया गया । मैंने अभी बतलाया था कि इन कारखानों में करोड़ों रुपये का लाभ होता रहा है लेकिन जिस तरह से वे यहाँ की पूंजी दूसरे उद्योगों में लगाते जा रहे हैं, इससे लगता है कि वे इन कारखानों को बहुत जल्दी सिक डिक्लेअर करने वाले हैं ।

मेरा आप से अनुरोध है कि आप तुरन्त इस में हस्ताक्षेप करके इन 15 हजार मजदूरों का बोनस भुगतान करायें, मजदूरों को परमानेन्ट करायें, पेपर इण्डस्ट्री में जो डिप्लायमेंट पूल की पालिसी चल रही है उसको समाप्त करायें और उनका जो भी पैसा इनकी तरफ बकाया है उसके भुगतान की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें । आप जानते हैं कि टैक्सटाइल इण्डस्ट्री में दो वर्ष तक हड़ताल चली, वह हड़तालों के इतिहास में एक अन-प्रेसिडेंटेड उदाहरण है और उसका परिणाम अन्ततोगत्वा यह हुआ कि उनमें से बहुत सी मिलें सिक हो गई और सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ा । इस तरह की स्थिति पैदा कराने में हमारे ब्यूरोक्रैटस भारी जिम्मेदार हैं । जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है, हमारे अधिकारी वर्ग का यह कर्तव्य हो जाता है— अगर किसी मिल ने समय पर लाभांश का भुगतान नहीं किया— तो उन्हें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । श्रमिकों की जो मांगे हैं उनकी तरफ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और उनकी जाँच पड़ताल करनी चाहिए और कहां सच्चाई है और कहां नहीं है, उसको देखना चाहिए लेकिन होता क्या है कि जब तक हड़-ताल नहीं हो जाती है, जब तक लाठी-डंडा नहीं चलता है और हंगामा नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होता है । इस प्रकार से सारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज रुग्ण पड़ी हुई

हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान खासकर रोहतास इंडस्ट्रीज की तरफ दिलाना चाहता हूं । वहाँ के मजदूरों की स्थिति भयावह होती जा रही है । इसलिए रोहतास इंडस्ट्री के मालिकों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और यदि वे लाभांस का भुगतान नहीं करते हैं, तो मजदूरों को कानूनन उस का भुगतान करगया जाना चाहिए और उसका राष्ट्रीयकरण किया जाया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर और भयावह स्थिति न बने । अगर राष्ट्रीयकरण बहुत देर के बाद करना पड़ा, तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा । अगर पहले ही उसका राष्ट्रीकरण कर देते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं हल हो सकती हैं और देश में दूसरे लोगों को भी सबक मिल सकता है ।

इसके अलावा बड़े बड़े पूंजीपति जो अपनी पूंजी का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ डाइवर्शन कर देते हैं, उसको भी रोकना चाहिए ताकि देश को राहत मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इस का समर्थन करता हूं ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सिकनैस के विषय में और उसके कारण के विषय में बहुत सारे मित्रों ने बहुत कुछ कह दिया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो हिली एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं या आई० आर० डी० सेक्टर में छोटे यूनिट्स हैं, उन में जो सिकनैस है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में जितना इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह भी प्रभावित हो रहा है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जो आर्गेनाइजेशन सेट-अप इन एरियाज के अन्दर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लाया गया है चाहे वे डी० आर० सीज हों, चाहे प्रोडक्ट कम प्रेसेस डेवलपमेंट सेन्टर्स हों या रूरल मार्केटिंग सेन्टर्स हों, यह सारा आर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है, इंडस्ट्रीज में जो प्रोमोशनल एटीट्यड डेवलप करना चाहिए थी, उसकी जगह पर ये एक प्रकार का ओब्सट्रक्शन क्रियेट करने का काम करते हैं । सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आप ने जो आर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन्स खोल रखी हैं डिस्ट्रिक्ट लेविल या तहसील के लेविल पर, इन का आऊटलुक बदला जाए और इन में ऐसे लोगों को रखा जाए, जिनमें एन्थूजियाज्म हो और जो न्यू जनरेशन आफ एन्टरप्रिन्योर को मदद कर सकते हों । इसके अलावा यहां पर जितने भी फाइनेन्शियन इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनसे क्रेडिट फ्लो जिस तरह से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और जो इन्सेन्टिव आप ने डेकलेयर किए हैं, वे इन्सेन्टिव्ज इन एरियाज की इंडस्ट्रीज को नहीं मिलते हैं और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स उनकी नीड्स को कैटर नहीं करती हैं । स्थिति आज यह है कि चाहे वे फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स स्टेट सेक्टर में हों या बैंकस हों, दोनों इन एरियाज में लगी हुई इंडस्ट्रीज की डिमान्ड्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके सामने किसी न किसी तरीके की दिक्कत खड़ी कर दी जाती है और आदमी पीलर टू पोस्ट जाते जाते थक जाता है और बैठ जाता है और जो पैसा उसका लगा होता है, वह पैसा भी डूब जाता जाता है । आप ने जीरो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स या नान-इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स को कुछ गाइडलाइन्स दे रखी हैं मगर उन सारी गाइडलाइन्स को लगातार वायलेट किया जा रहा है । इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।

इसके अलावा इन एरियाज के अन्दर जो नवीनतम टेक्नोलाजी होनी चाहिए, उस टेक्नोलाजी का ज्ञान देने के लिए, लोगों को टेक्नोलोजी की नौहाऊ देने के लिए ऐसी मैनपावर

वहां पर उपलब्ध नहीं है, जिससे वहां पर बड़ी दिक्कत आ रही है। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर रो-मैटीरियल एवेलबिल नहीं हैं। बैकवर्ड एरियाज में ए. बी. और सी आइटम्स की इंडस्ट्रीज लगा दी जाती हैं मगर रा-मैटीरियल कैसे मिलेगा, समय पर उसकी आपूर्ति कैसे कराई जाएगी, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास ऐसा कोई आर्गेनाइ-जेशनल सेट-अप नहीं है, जो इस चीज को देखे कि जो चीज वहां पैदा होती है, उसकी टाइमली मार्केटिंग कर सके। इसका बहुत बड़ा अभाव वहां पर है। इसलिए बहुत सारी इंड-स्ट्रीज में बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज और रिमकैट एरियाज में सिकनैस डेवलप हो रही है और इस तरह से जो इन एरियाज में एक इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट पैदा होनी चाहिए थी, वह इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट पैदा नहीं हो रही है। मैं यह जानता हूं कि इंडस्ट्रियल सिकनैस को रोकने के लिए गवर्नमेंट तत्पर है और इस दौरान इस दिशा में उद्योग मंत्रालय के द्वारा बहुत कुछ कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डिक्लाईन हुआ है। 1981-82 में 8.6 परसेंट से घटकर 3.7 परसेंट पर आ गया वर्ष 1982-83 में। इससे साफ है कि हमारे यहां कहीं न कहीं उद्योगों में रुग्णता पैदा हुई है, कहीं न कहीं इनमें सिकनेस आई है। उद्योगों में रुग्णता आने के कारण साफ दिखाई दे रहे हैं; यह जो प्रस्ताव आज हमारे सामने है यह बहुत समय से आया है और इसका मैं समर्थन करने जा रहा हूं।

उद्योगों में रुग्णता के बहुत से कारण हो सकते हैं। पावर शार्टेज की बात कही जाती है। कहीं टेक्नोलोजी के, तकनीकी के अभाव की बात कही जाती है और कहीं रिसोर्सिज की बात कही जाती है। जबकि ये सारी चीजें हैं लेकिन आपके फिगर्स के मुताबिक ही 422 बड़े औद्योगिक यूनिट सिक लिस्ट में हैं और 23,848 छोटे यूनिट सिक लिस्ट में है। 1970 में आपके 345 बड़े और 16,800 छोटे यूनिट सिक थे। आपने इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो तरक्की की है वह इन्हीं फिगर्स से साफ जाहिर हो जाती है।

इनके बहुत से कारण बताये जाते हैं कि पावर शार्टेज और रिसोर्सिज आदि की कमी है। लेकिन मैनेजमेंट के बारे में सरकार ने भी खुद स्वीकार किया है कि 52 परसेंट आफ सिकनेस इज ड्यू टू द फैक्ट इन मैनेजमेंट ओर मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट की वजह से आपके 52 प्रतिशत यूनिट सिक हैं। यही नहीं, पब्लिक सैक्टर यूनिट्स की बात को देख लीजिए जिनको कि सरकार खुद संचालित करती है। उनमें 15 यूनिट्स बड़े हैं जिनकी कि हालत ऐसी है, जैसा कि डागा साहब सरकारी पक्ष से बोल रहे थे कि उनमें दो हजार करोड़ रुपया लोसिज में चला जाता है ऐसी हालत आपके पब्लिक सैक्टर यूनिट्स की है।

मान्यवर, मैं नेशनल टेक्साटाईल कार-पोरेशन, एच०सी०सी०, ईस्टर्न कोल फील्ड्स, हिन्दुस्तान कोपर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आप इंडिया के बारे में कहना चाहता हूं कि इनमें से अधिकांश यूनिट्स सिक रहते हैं। इनमें बैंकों का, फाइनेंशयल इंस्टी-च्युशन्स का दो हजार करोड़ रुपया फंसा हुआ

है। पता नहीं इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर में उस सिक यूनिट को तब लेते हैं जबकि वह बिल्कुल सिक हो जाता है। कोई व्यापारी या उद्योगपति कोई यूनिट लगाता है तो वह जब तक तो उसको चलाता है जब तक कि उससे अपना सारा पैसा नहीं निकाल लेता। अपना सारा पैसा निकाल लेने के बाद वह उसमें तालाबंदी कर देता है यह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अन्य तरीके अपना ने लगता है। क्या इससे आपका ग्रोथ रेट कम नहीं होता है ? ये एसे प्रश्न हैं जिनको कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तिवारी कमेटी की जो रिकमण्डेशन्स मेनेजमेंट के सम्बन्ध में आई है कि एक ऐसी बोडी बने जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मोनिटरिंग करे, क्या आप ऐसा कोई लेजिस्लेशन या अधिनियम बनाने जा रहे हैं ? आप क्या करते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर के सिक यूनिट को लेते हैं और उस हालत में लेते हैं जब वे बिल्कुल खत्म होने को होते हैं, फिर उनका आधुनिकीकरण करके, कभी कभी उस यूनिट के मालिक को वापिस कर देते हैं। यह एक अजीब तरीका है। जब किसी यूनिट की इतनी बुरी हालत थी और आपने उसको लेने के बाद उसकी हालत सुधारी तो फिर उसी उद्योगपति को क्यों दे देते हैं ? आप व्यापारियों का और उद्योगपतियों का कर्ज भी माफ कर देते हैं और देश के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग होता है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि तिवारी कमेटी की जो रिकमण्डेशंस है उन पर अमल करने का आप फैसला करें। क्या आपने अब तक यह फसला किया है या नहीं ?

मैं एक बात इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशंस एक्ट के बारे में कहूंगा। इस एक्ट को अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसको संशोधित करने की जरूरत है। इस एक्ट में किसी राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, उनके ऊपर कोई लाएब्लटी नहीं डाली गई है कि किसी यूनिट में इतना पैसा लग जाने के बाद अगर वह बुरी हालत में चलता है और राज्य सरकार उसको देख रही है लेकिन उस मामले में वह कोई दखलनदाजी नहीं कर सकती और न सुझाव दे सकती है।

ऐसी परिस्थितियों में इस एक्ट को संशोधित करना चाहिए और तिवारी कमेटी की सिफारिशों को कब तक अमल में लाया जाएगा ? मजदूरों का शोषण रोकने केलिए क्या करने जा रहे हैं ? अगर नहीं करेंगे तो आपका समाजबाद का नारा थोथा साबित होगा। इतना कहते हुए मैं इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। श्रीमन् उद्योगों की बीमारी के संबंध में जो प्रस्ताव मेरे सम्मानित मित्र सदस्य श्री बालानंदन साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता था कि इस पर 10-12 घंटे चर्चा हो। क्योंकि आज जब उद्योगों की ओर देखते हैं तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों की हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर के संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो रुग्णता आ रही है वह उद्योगपतियों की चालाकी की वजह से है। मेरा ऐसा विचार है कि उद्यमी उद्योग लगाते हैं और सरकार से पैसा लेते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं। जग खूब कमाई कर लेते हैं और उससे दूसरा-तीसरा उद्योग लगा

लेते हैं तो उस उद्योग को चौपट करना शुरू कर देते हैं। मजदूरों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उस उद्योग का मेंटिनेंस ठीक तरह से नहीं करते ताकि किसी तरीके से उद्योग बंद हो और सरकार इसको अपने हाथ में ले ले। सरकार क्या करती है। सरकार गलती करती है। उद्योगपति हिसाब-किताब लगाकर दे देते हैं कि उस जमाने में उद्योग की कीमत इतनी थी और आज इतनी कीमत है। चार गुनी ज्यादा कीमत बता कर सरकार से पैसा ले लिया जाता है और यह मार सरकार पर पड़ता है। सरकार जनता की है इसलिए जनता पर मार पड़ती है। पूंजीपति मालामाल होता है।

आज उद्योगों की रुग्णता वास्तव में एक रोग बन गया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। आप सरकारी क्षेत्र में देख लीजिए। सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी घाटे में चल रहे हैं। घाटे में क्यों चल रहे हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। मेरा अपना निजी मत है कि यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों का षड़यंत्र है। जब आपने समाजवाद का नारा दिया तो जनता ने नारा दिया कि उद्योगों का राष्ट्रीकरण होना चाहिए। तब टाटा, बिड़ला और बड़े पूंजीपतियों ने एक षड़यंत्र रचा और पब्लिक सेक्टर में चलने वाले उद्योगों को फेल करने के लिए साजिश की गई। उनका उत्पादन गिरता है, उनमें काम सही नहीं होता। पब्लिक सेक्टर का मैनेजर मशीनरी लेने जाता है तो उनको कमीशन मिलती है, वह कमीशन लेता है। प्राइवेट सेक्टर का मैनेजर मशीनरी लेने जाता है तो कमीशन नहीं लेता। और वह मशीनरी पब्लिक सेक्टर के कारखाने में 1 साल में खत्म हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर में दसियों साल काम करती है और उससे लाभ कमाया जाता है। एक कारखाने से दो और दो से तीन कारखाने बनाए जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है ? इस पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह रुग्णता जो पनप रही है, फैल रही है यह देश के आर्थिक विकास के लिए, इस देश की सरकार के लिए, इस देश की जनता के लिए, 70 करोड़ लोगों के लिए अभिषाप बनकर रह जाएगी और चन्द घरानों का महत्व बढ़ता जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस देश से अंग्रेज चले गए। अब ये चन्द घराने राज कर रहे हैं। चंद घरानों में इस देश की पूंजी इकट्ठी हो गई है। देश की पूंजी पर चंद घराने काबिज है और सारा देश तबाही की कगार पर खड़ा है। ऐसे ऐसे तरीके बनाए जा रहे हैं। सभापति जी, आज हम इस सदन में खड़े हैं कि सरकार को आगाह करें। आप अगर निश्चित रूप से हमारी राय चाहते हैं तो यह चालाकी की बात है और इसको हमें देखना चाहिए। आप इसको देखेंगे। तो कुछ करेंगे। अगर इनकी मिली भगत है तो ये धंधे ऐसे ही होते रहेगें और आप कभी इनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे।

हमारे यहां दो शुगर फैक्टरियाँ हैं, उनमें एक लक्ष्मी शुगर मिल मडोली का अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके अधिग्रहण करने के बाद करोड़ों रुपये का माल खरीदा गया, कल पुर्जे खरीदे गए, लेकिन अब भी वह घाटे में चल रही हैं। वहां के मजदूर लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरह के उद्योग चल रहे हैं। उनको पब्लिक सेक्टर में लाने की साजिश की जा रही है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं।

मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आंकड़े देकर बताता कि कहां-कहाँ किस तरह की साजिश चल रही है।

यह साजिश आपकी मिली भगत से इसलिये चल रही है कि आपको चन्दे की जरूरत

है, अगला चुनाव लड़ना है और इसके लिए आप उद्योगपतियों से सांठ-गांठ किये हुए हैं, चाहे टैक्सटाइल मिल या जूट मिल को अधिग्रहीत किया जाये, लेकिन ऐसा करते समय यह देखिये कि मिल मालिक पहले क्या था और आज क्या है ? अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो देश की जनता का भला करेंगे और अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसकी पूंजी और लागत को 4 गुना आप बना देगे और इस तरह से देश की जनता लुटा देंगे ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI S.M. KRISHNA) : Mr. Chairman, Sir, the Resolution moved by my esteemed friend honourabln Shri Balanandae, focuses attention on a matter which has aroused considerable interest. A critical analysis has been made by a number of speekers on this Resolution and they have tried to pin-point and diagnose the reasons for industrial sickness and also they have tried to provide solutions in order to arrest sickness at the inittial stage itself, if not to prevent it totally.

Sir, in an economy which is growing and whidh is poised for growth, industrial sickness need not necessarily be blown out of proportion. When I make this submmission to this august House, I do not mean to denigrate the enormous toll that industrial sickness is taking on our national economy. Bearing that in mind, the limited point that I am trying to make out is that with the industrial growth there is bound to be a certain degree of industrial sickness and this is true of not only developing countries, but this is also true of most other countries of the world. I can quote instances where big multinational companies have folded up in developed countries. Closure in a developing country makes a greater impact than perhaps in a developed country. So, it is in this perspective that I would beg of this House to look at the incidence of sickness of industries in the Indian economy and appreciate the efforts that the Government is making (a) to prevent sickness, and (b) to nurse sick industries back to health. These are twin premises on which the industrial policy of the Government of India has been designed.

Sickness can be attributed to a number of factors. Some of them could be external factors. Some of them could be internal factors. The external factors could possibly be the demand recession. An industry can be promoted with a particular projection of demand -May be in the next five years or ten years and for a number of reasons if there is a recession in demand, then the natural corollary of a situation like that would be that an industry which caters to that particular demand is bound to be sick.

Then there could also be shortage of raw materials and scarcity of power. These two are inter-linked. Now if a particular raw material is dependent upon the power supply in a given State, then naturally all those units which are dependent upon the raw material which they are hoping that they would be provided or would be available from out of that unit will be stalled because of the non-availability of raw material.

17.03 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*)

As regards internal factors it has been freely mentioned -almost every speaker without any exception has made the point with telling effect that the major internal factor for internal sickness is inefficiency or dishonest management. Diversion of resources, utilisation of current assets for non-current and long term purposes, obsolescence of technology and machinery, etc. are there.

Diversion of funds is one of the many factors which take a very heavy toll on an industry. The Reserve Bank of India has made a sarvey and a number of hon. Members including the Mover of Resolution Shri Balanandan has drawn the attention of the House. The survey which was made by the Reserve Bank comes to this conclusion that about 52% of the units have gone sick due to internal causes like mis-management, management deficiency

including deficiency of funds, infighting, lack of marketing strategy. About 14% of the units have gone sick due to faulty initial planning and other technical drawbacks which carried on to the first category of inefficient management. If it is a faulty planning, then certainly it is a reflection on the management itself. Only 2% are on account of labour trouble. This is in my humble opinion a very redeeming feature of the whole scenaries. 23% of the units have gone sick due to market recession and ıe rest of the 9% could be on account of power cuts, shortage of raw materials or various other things.

Now, in a situation like mismanagement of unit, diversion of funds, an impression was sought to be created by a few hon. Members including the last hon. Member who participated in the debate and they seem to be under the impression that whenever a unit is mismanaged, either it is closed or taken over by government. They seem to labour under the mistaken nation that the government pays compensation. I am sure his appreciation of either taking over of the unit or closure of the unit is certainly much to be desired. Well, it is not anybody's case that government gives compensation. Govenment does not. But Government certainly does play its role in trying to nurse sick units back to health. Keeping this in view, after the present government came into power, in October, 1981, a policy for sick industries for the first time was authoritatively laid down. And this policy which was laid down in February, 1982 pins a pivotal role on the administrative Ministries to keep a close watch on the state of health of the units which come within their purview. Monitoring arrangements have been taken up and remedical action either from the banks or financial institutions whenever it becomes necessary is taken. Government's assistance wherever it is warranted is given and utimately nationalisation comes if the unit provides ample scope and opportunity to be received.

Now the government considers a unit as a sick when we draw negatively on some of the aspects where there are no profits, the net worth is negative and the availability of capital is totally erroded and it also becomes negative. Then, we take up a diagnostic study and here the banks have a crucial role to play. It would be unfair and uncharitable to say that the banks have not been playing that role. Well, there might be slippages here and there. But when you look at the totality of the picture, perhaps if I can quote a few figures that will drive home the point that how the banks have tried to nurse units back to health. Those units which were not viable have been made viable by the banks and by the intervention of the banks. I would like to quote for my friend Shri Balanandan's reference that as of 30th June, 1982, the total number of large and medium industries was 1,455 and out of which viable units were 714. Non-viable un its were 495. With reference to 176 units, viability was yet to be decided. The units out on the nursing scheme were 623 and in terms of percentage 61.3% of the units were found to be viable. With reference to small scale industries, there were about 26,905 which are the total number of units out of which 27% were made viable.

Now, the point that I was trying to make was, if the units are delected from the list of sick units, it should throw sufficient light on the Government's effort through the banks, through the financial institutions and through the administrative Ministries, in that direction.

During January-December, 1981, 208 large units with an outstanding credit of Rs. 128.73 crores were deleted from the list of sick units, and during, January-June, 1982, 107 large units with an outstanding credit of Rs. 55.59 crores were deleted from the sick list. As regards small-scale units, during January. December, 1981, 6624 with an outstanding credit of Rs. 52.40 crores were deleted from the list of siek units and, during January-June, 1982, 1321 units, with an outstanding credit of Rs. 18.35 crores were deleted from the sick list.

The point that is to be appreciated is that there are a number of units which are being deleted from the sick list. This is a healthy development. But simultaneously there could be more units which would be coming within the bracket of sick units.

This is a phenomenon which cannot be helped in the kind of industrial growth that is taking place in our country.

So, I have got the details about the large units which have been deleted from the sick list and I have also got the categories of industries where the incidence of sickness is a little more than in others.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) : May I just refer to the large, medium and small scale sick units of West Bengal where I have given facts and figures because that is the most disturbing area ? Therefore, you may throw some light on that aspect as well.

SHRI S.M. KRISHNA : Let us take the jute industry as such which is predominently concentrated in West Bengal. Coming from the neighbouring State, you do realise the apathy and the plight of the jute industry. There has been total disregard for modernisation of jute industry as a result of which the entire jute industry has become sick. When a whole sector becomes rich, certainly, in terms of percentage index, it makes a greater dent on the sickness of the industry PER SE.

Also, about textiles, the House has debated a number of times about the sickness in the textile industry. So also about steel industry and rubber industry. There could be a number of reasons as to why there has been a greater incidence of sickness in a particular sector. I would not like to dilate on that.

With reference to the point that has been made by my hon. friend, Mr. Arakal, about West Bengal, nobody denies that the incidence of sickness is perhaps the highest in West Bengal.

There are historical reasons and perhaps all the approximately 25% of the large industries which are situated in West Bengal.

I am not trying to throw the blame on anybody.

If you want the details, I have the details with me.

State	No. of sick units
West Bengal	106
Maharashtra	84
Uttar Pradesh	55
Gujarat	37
Tamil Nadu	34
Karnataka	20

Like that it goes on.

A reference was made by some Hon. Members to the Tewari Committee which was appointed to go into the question of of sickness of industries.

It is a fact that the Tewari Committee has made certain recommendations. The various recommendations of the Tewari Committee regarding special legislation for sick units are under the active consideration of the Ministry of Finance. The matter requires to be considered in consultation with various administrative Departments and that is being undertaken by the Ministry of Finance. It has also been proposed to discuss the matter in a meeting to be convened shortly so that the decisions on the various recommendations could be taken early and it could be a step forward in trying to meet the challenges that are posed by the incidence of sickness.

In the course of the debate, a number of Hon. Members have made references to individual industries and I do not know whether I should take the time of the House.

MR. CHAIRMAN : Then sickness will spread to the House itself ;

SHRI S. M. KRISHNA : For example, my friend Mr. Daga.....

SHRI XAVIER ARAKAL : The Hon. Minister can refer to the industries which were mentioned by the Hon. Members who are present in the House.

MR. CHAIRMAN : And who are not affected by sickness ;

SHRI S. M. KRISHNA : A reference was made to the Jaipur Spinning and Weaving Mills which is a sick unit which has been incurring fiinacial losses since 1974. We have come to know that the reasons are recession, lack of modernisation and replacement of machinery. These are the causes for sickness.

Another Hon. Member made a mention about Mewar Textile Mill which is a marginal Unit incurring losses only in some years. The management already expansion of modernisation scheme.

Some Hon. Members made reference to Krishna Mills, J. K. Rayon and so many other mills.

SHRI XAVIER ARAKAL : I mentioned about the Binni Company and the Auto Friction of Trivandrum and I insisted on getting a reply on these two when I referred.

MR. CHAIRMAN : I hope, looking to the situation as it is in the House. let us try to be brief.

SHRI S. M. KRISHNA : I appreciate Hon. Member Shri Xavier Arakal' concern about the Binni Company and I will keep the Hon. Member informed about what action Government has taken in this regard.

The Hon. Member Shri Xavier Arakal has also made certain important suggestions and one of the suggestions is to convert certain provident fund dues and statutory liabilities in to equity in a unit. This takes us to the larger question where this cannot be done by legislation. This can only be done by a consensus if it can be worked out with various trade unions in the country and primarily with the workers who are involved in a Unit.

Also my friend, Shri Daga, has moved an amendment; it pinpoints the problem of multiplicity of unions in a particular industry which again takes us to a much larger question of indusrial sickness. It is the endeavour of the Government to prevent sickness and to arrest sickness, to diagnose it, to monitor it, constantly, and in this task the administrative Ministries, the banks and the financial institutions have been playing their role. If there are individual cases were the role that has been played is not enough to meet with the emerging challenges, certainly Government would be too willing to look in to that particular question.

With these words, I would say that we do not have any differences, I understand the concern with which Shri Balanandan has moved this Resolution and I hope, in view of my reply, where I share the concern of the entire House, he will not insist and withdraw his Resolution.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram) : Sir, the Minister of State for Industries has given a reply which is really within the policy framework of the Government, absolutely a reasonable reply for which I must thank him first, but I am sorry to say that this will not be sufficient to meet the situation. He has also promised that, if things are so serious, further steps will be considered by the Government. On that basis I am now coming to certain problems and I am going to suggest some remedies.

Before coming to the hon. Minister's reply I must thank the hon. Members who have taken so much of interet to discuss this question, all sides of the problem have been brought before the House, and I must thank all of them for that. My friend, Mr. Arakal, is here; he has made very big suggestions; I do not want to deal with them now. Also in the Minister's reply some larger questions have also been brought in, and if I go to dilate on them, it will take a little more time. So, I am not going into those now. I will confine myself to the real change in the policy framework which is required.

While placing the Resolution before the House, I have requested the House to exercise its discretion and impress upon the Government to come out with a new policy framework, so that this incidence of industrial sickness leading to lakhs and lakhs of workers to unemployment can be checked. This was my intention.

Coming to the different suggestions made by the hon. Members and the hon. Minister, one or two industries I want to make a special mention of which will reveal what is India's recessionary trend which makes many industries sick. As you know, our country was, even during the British days, famous for one thing and that is. the textile industry. Indian hawkers were there in Manchester, the city of the textile industry, selling the Indian goods and the British buyers used to come and ask for the Indian goods. We had the famous Indian textile industry which was dominating not only in India but even in Great Britain, in Manchester too. But what is the position of this industry. today. This industry is facing a serious crisis in this sense - I do not want to, go into much of your figures because you will be very restrictive in reply.

In public interest we had to nationalise nearly 112 mills, that is, 17% of the Industries' total spindlage and 25% of the total loomage has been nationalised by Government. In the private sector, 25% of the spindlage and 30.5% of the loomage have been facing a crisis to-day. Taken these two together, 45% of tde total spindlage of the spinning and 60% of the weaving capacity are more or less in the crisis list. Look at the situation. Take for example Bombay Textile Mills strike. On third of the textile production was not there for nearly 1/1-2 years to 2 years. Afterwords, what is the present day situation ? Even after the Bombay textile strike the textile goods produced were there—was no dearth of these goods—the millowners could not rise their price. They were announcing the concessions in price because of no offtake. To-day you will find that the stock position in the textile industry is alarming. The total stocks with the organised sector of cotton textile industry rose from 1.62 lakh bales in August 1982 to 2.02 lakh bales by August 1983—25% rise. This accumulation of stocks has taken place despite the estimated loss of 1300 billion meters due to the Bombay Textile Mills strike. The situation worsened further in October when the yarn stocks with the mills went up from 27.4 million K.Gs. in May this year to 31.3 million K. Gs in October. The accumulated stocks with the mills have gone up by as much as 100 million meters—from 249 million meters to 353.3 million meters between May and October. These figures tell us that there is a serious situation. You may say that I am talking about the mill sector. May be the other sector may be compensating. This is the total situation. The consumption of cloth is also coming down. Why is it so ? It is because the totality of the purchasing power of the people is going down. The textile goods are being consumed by 75% of the peasantry. They have no money, they need food first and then the cloth. That is so for every human being in the country. The per capita consumption of cloth is going down. Therefore as you rightly pointed out, the industry will go on like this since the recessionary trend comes in. This is the fact. I do not want to go into all the industries. Take the jute industry. The Minister also was kind enough to mention about the jute industry. What is the position of jute industry ? Nearly 16 mills were closed as you correctly pointed out. Five Families control the whole of the jute industry where 2 lakhs workers are employed such as Bajoria, Kanoria, Jhunjunwalla etc. They control the whole industry. Two lakhs workers are employed in these industries. The industrialists are making huge profits but, to our bad luck or for the capitalists' greed for profits alone, they do not think of the nation or the people, they did not invest properly, they did not modernise the industry or diversity production. They did not do it. They have only done this method of pocketing the money for doing some other business somewhere. They did not make any investment where the industry is situated. There fore, 16 industries were closed. 8 of them have been re—started. Now thousands and thousands of workers are without work in West Bengal. Why is this so? This is because of the private management who were holding sway over this industry. They had no concern for the State or for the nation or for the country or for the people. That is the question which the trade union ask. They are being forced to ask that question. For industrial sickess, a remedy has been suggested by the hon. Minister. That is all right. But will this remedy suit us here, will this remedy solve the problem ? The whole money has been taken away by them and squandered away

by them; lakhs and lakhs of workers are not getting anything. The solution for the problem in the jute industry's nationalisation,

Sir, I will deal with this point quite elaborately a little later.

MR. CHAIRMAN : Already you have taken 10 minutes. If you elaborate, there will be no time for that.

SHRI E. BALANANDAN : I aay, the only remedy, therefore, is nationalisation.

Then, coming to other industries, what is the position ? My friend Mr. Arakal was telling about Kerala State. He was referring to a mill in Kerala. It is a small thing. You know, Kerala is a State where there are no industries. Only agro-based industries are there. Coir industry is there. Cashewnut industry is there. Lakhs are employed in coir industry. What are they getting ? Nothing, They work, but nothing to eat ; That industry is in doldrums. In cashew industry some experiment was made by the earlier Government, to see that the industry works. To our bad luck, it has been demolished. So now lakhs and lakhs of cashew workers are in doldrumf. I don't want to say anything about Kerala. My friend Mr. Arakal was making a point. He is my best friend He is always sincere. I don't want to say anything. Here this 17 per cent sickness comes in. Dont't go to 25 per cent. That is official figure. Where the industies are more, and small industries are more.

SHRI XAVIER ARAKAL : On a point of clarification ; I only wanted to cite an example. I am not directly oi indirectly abusing anybody. I was only highlighting the point.

SHRI E. BALANANDAN : Don't give an bad impression, any wrong impression,-I am only saying that.

MR. CHAIRMAN : You want to know why West Bengal is sick. That is all.

SHRI E. BALANANDAN : My friend Shri Arakal need not go with the impression that because of something else, it is happening because of the totality of the situation. It should not be looked at that way.

Coming to other things, Sir, Mr. Narayan Choubey made a point, which needs your absolute attention. He brought out a point based on the statement made by Swaraj Paul-he is a man in the news nowadays. What is this statement ? I quote:

> "11 industrial hoses in India (Bharat) control 25,000 crores of public money, bank money and their investment is 2.5 per cent in industry."

Mr Arakal was saying about socialism. What kind of socialism have we ? Now, I can give you another list. That list is about the MRTP Act.

MR. CHAIRMAN : Don't look to that side ; if you speak more of Mr. Arakal, you will have no time.

SHRI E. BALANANDAN : I was only saying, many of us are confused about Socialism. Mr. Araakal is my friend.

MR. CHAIRMAN : He is a good member.

SHRI E. BALANANDAN : Here, Sir, my point is this :

He said that eleven big houses control the public money, that is the money of yours and mine to the tune of 25000 crores, and their own investment is only 2.5% I do not want to say anything about their investments abroad. I am having a list of big houses ; ninety two names are there. What is the investment of public funds from banks, IDBI and other institutions. Out of these 92 companies, in 55 companies, the public sector share in equity comes to more than 33.3%. Now, according to the MRTP Act, if the investment of public sector share in equity is more than 33.3%, it can be considered as a public sector institution. That is the point I am making. When I say that you should nationalise them, I am

saying that as per the rules and the Act, and the investment of the Government of India made through various sources. Why do you allow these Nandas, Escorts and other fellows to manage these companies ? Is it only they who have got the expertise ? According to the list with me, the public sector share in equity in Tata Engineering and Locomotives Co., Tata Iron and Steel Co., and Tata Power Co. is 44.84% 42.25% and 38.40% respectively, and their investment may be 2, 3 or 4%. And I have such a list with me, the companies are 55 in number.

I do not want you to bring socialism immediately ; it is impossible to be implemented by you. Then, why should I ask you ?

Now, one factory was closed where 3500 workers were employed Within six months, nine of them died of starvation. Are you going to treat the employers and the workers on equal basis ? While the workers do not have money even for a day's living, the employer has amassed crores of rupees. And the employers have no investment there, only mismanagement is theirs. Therefore, the way the Government looks at this question is a wrong and wrong way of looking at it. Everybody says that the workers are the wealth of nation, they are the real producers of wealth, but in practice how do you treat them ?

In view of this situation, the present kind of Birla, Tata socialism should not go on for long. The present socialism can only be termed as Birla, Tata socialism and nothing else.

Unless we have the will and bring about drastic changes, we cannot solve the problem So many changes are required in the Government's policy. If you want to arrest the incidence of industrial sickness, a major policy shift is required. Those industries which are on the sick list are to be individually examined.

One of the basic point to be noted is that the workers who are employed in the factory should be provided with alternative employment. He must be allowed to live. That should be ensured before the take-over of the mill.

The 25th Indian Labour Conference stated that the legislative provisions of the Governmental machinery for take over of sick units should ensure continuity of employment and production. Consequent upon the take-over there should not be any redduction in employment or emoluments. Nor should there be any adverse effect on the service conditions and benefits.

This is the recommendation of the 25th Labour Conference. I have on information that in West Bengal the Government have taken over four industries as per the Industries' Development Regulation Act. Now we are told that the Government wants to denotify Carter Tooler Co. Ltd., Containers & Closers Ltd., Indian Rubber Manufactureres Ltd., Machinery Manufacturers Limited. In these factories 10,000 workers are employed. And Sir, I have quoted the recommendation of the 25th Labour Conference. Then the Government is saying that such and such steps are being taken, but the West Bengal Government says you should not do it. Now, 10,000 workers are on the street. While I was referring to the take over of the jute industry, my friend was saying that Rs. 1400, crores of provident fund should be converted into equity share. Rs. 1400 crores is the workers' money. Nobody should take that.

Therefore, I am requesting the Hon. Minister only two things. I don't say all the industries should be nationalised. But at least the textile industry and the jute industry should be nationalised. Of course, 13 mills of the textile industry in Bombay you have taken over and it is an appropriate step. I thank you for that. For taking over of the jute industry the demand is not from the Communists. This is the demand of Mr. Anand Gopal Mukherjee of the Congress (I), our friend of West Bengal. Chitta Basu and Mr. Mukherjee urged the Government of India to nationalise the jute industry. I hope the Government will consider this suggestion seriously within the policy framework.

Since the Chairman has put restriction on time, I would only request that the complete sick industries should be taken

over especially in the textile and jute sector. I also told you that Rs. 25,000 crores invested in monopoly houses of these eleven people as I mentioned, should be nationalised.

With this I request the Hon. House that my Resolution may be unanimously accepted.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Amendment moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"This House expresses its deep concern over the increasing incidence of industrial sickness and consequent developing crisis in industry, which is resulting in lay-offs, lock-outs and closures affecting millions of workers and employees and resolves that the Government do take urgent and appropriate steps to remedy the situation."

The Motion was negatived.

RESOLUTION RE: UNEMPLOYMENT

MR. CHAIRMAN : New we go to the next Resolution. Mr. T.S. Negi, you may move it.

श्री टी. एस. नेगी (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की भूमि सेना का निर्माण करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करे—

(क) बड़ी नदियों के तल गहरे करने का कार्य ;

(ख) हिमालय क्षेत्र सहित समूचे देश में वनरोपण कार्यक्रम इस प्रकार चलाना कि भूमि का कम से कम एक–तिहाई भाग वन प्रदेश हो ;

(ग) व्यापक भूमि संरक्षण कार्यक्रम;

(घ) देश की बड़ी नदियों को दूसरी नदियों के साथ मिलाना; तथा सिफारिश करती है कि सरकार को सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कम से कम 100 रुपये प्रति मास बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने चाहिए ।

श्रीमन्, आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर हो चुकी है । हम यह नहीं कह सकते कि कितने बेरोजगार नौजवान प्रति दिन खुदकशी कर रहे हैं और कितने लोगों ने बेकारी के कारण गलत धंधा करना शुरू कर दिया है । ये सब बातें बहुत चिन्ता का विषय है ।

भारत वर्ष में आबादी का औसत घनत्व लगभग 375 प्रति-वर्ग मील है । किन्तु यहां पर घनत्व से, ताल-मेल बिठाते हुए औद्योगीकरण नहीं किया गया है । रूस, जर्मनी अमरीका और ब्रिटेन आदि मुल्कों की तरह मशीनों को अपना कर मानव-श्रम की उपेक्षा की गई है । हमारे मुल्क में जो प्लानिंग हुआ है, वह मानव-श्रम को दृष्टि में रख कर नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ करेन्सी के आधार पर प्लानिंग किया गया है और उसमें देश के मजदूरों, कार्य करने वालों, को नजर-अंदाज किया गया है । हमारा देश एक खेती-प्रधान देश है; परन्तु फिर भी गांवों की तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बेरोजगार हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं; इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और उनकी समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं ।

हमारे देश में शुरू से ही कच्चा माल विदेशों को भेजा गया है, जिसका उद्देश्य